2020 में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का विश्लेषण

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 31 जनवरी, 2020 को संसद को संबोधित किया था।[1]अपने अभिभाषण में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की मुख्य नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित किया था। निम्नलिखित तालिका में राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुख्य विषयों और उन विषयों के संबंध में की गई पहल की मौजूदा स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। 18 जनवरी, 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इस नोट को तैयार किया गया है। आंकड़ों के स्रोत एंड नोट्स में दर्ज किए गए हैं।

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	अर्थव्यवस्था एवं वित
भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।	▪ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, भारत मौजूदा मूल्यों पर जीडीपी के लिहाज से छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था जोकि 2.59 ट्रिलियन USD अनुमानित है।[2,3] 2019-20 में 4.2% की वृद्धि की तुलना में 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि दर में -7.7% की गिरावट का अनुमान है। सरकार ने कहा था कि कोविड-19 महामारी और मार्च, 2020 से लागू लॉकडाउन संबंधी उपायों ने मुख्य आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 2020-21 के लिए 134.4 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का अनुमान लगाया है जिसकी वर्तमान विनिमय दर (INR 72.9/USD) 1.84 ट्रिलियन USD है।[6]

तालिका 1: कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि दर (2011-12 के मूल्य पर)[4,5,6]

वृद्धि दर	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कृषि	4.8	5.4	7.9	5	2.1	3.4	3.4
मैन्यूफैक्चरिंग	6.5	7.1	8	6.7	7.6	0.03	-9.4
सेवा	9.6	9	8.5	8.6	7.6	3.6	-21.4
जीडीपी	7.4	8	8.2	7.2	6.8	4.2	-7.7

नोट: कृषि में कृषि, वानिकी, और खनन, मैन्यूफैक्चरिंग में मैन्यूफैक्चरिंग, निर्माण, और बिजली एवं जलापूर्ति, तथा सेवा में व्यापार, परिवहन, वितीय, रियल ऐस्टेट और रक्षा सेवाएं शामिल हैं।

श्रुति गुप्ता
shruti@prsindia.org

27 जनवरी, 2021

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td>विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह में वृद्धि।</td><td>

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई): 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में एफडीआई प्रवाह 30 बिलियन USD रहा, जबकि 2019-20 और 2020-21 में इसी अवधि के दौरान यह क्रमशः 26 बिलियन USD और 22.7 बिलियन USD रहा।[7,8,9]

तालिका 2: 2015-16 और 2020-21 के बीच एफडीआई प्रवाह[7]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21 (सितंबर तक)</th></tr>
<tr><td>एफडीआई प्रवाह (बिलियन USD में)</td><td>40</td><td>43.47</td><td>44.85</td><td>44.36</td><td>49.97</td><td>30</td></tr>
<tr><td>वृद्धि का %</td><td>35%</td><td>9%</td><td>3%</td><td>-1%</td><td>13%</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन USD से अधिक की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा।</td><td>

विदेशी मुद्रा भंडार: जनवरी 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 585 बिलियन USD पर पहुंचा, जोकि जनवरी 2020 में 467 बिलियन USD के मुकाबले 27% अधिक है।

तालिका 3: प्रत्येक वर्ष जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार[10]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr>
<tr><td>विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन USD में)</td><td>349</td><td>360</td><td>414</td><td>397</td><td>461</td><td>585</td></tr>
<tr><td>पिछले वर्ष से परिवर्तन का %</td><td>8.4%</td><td>3.2%</td><td>15.0%</td><td>-4.1%</td><td>16.1%</td><td>26.9%</td></tr>
</table>

विदेशी व्यापार: अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच भारत के निर्यात में 2019 में इसी अवधि की तुलना में 12.65% की गिरावट हुई और यह 348.49 बिलियन USD हो गया। इसके अतिरिक्त आयात में 25.8% की गिरावट हुई और यह 343.2 बिलियन USD हो गया।[11]

</td></tr>
<tr><td>121 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं।</td><td>

18 जनवरी, 2021 तक 127.8 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए (2020 के लिए अनुमानित जनसंख्या के आधार पर भारत की 96% जनसंख्या)।[12]

</td></tr>
<tr><td>38 करोड़ गरीब लोगों के लिए बैंक खाते खोले गए।</td><td>

6 जनवरी, 2021 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 41.6 करोड़ खाते खोले गए (2014 में प्रारंभ)। इसके अंतर्गत कुल 1.35 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा हुई। इनमें से 65% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए।[13]

</td></tr>
</table>

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति

तालिका 4: जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते[13]

मानदंड	जन-2017	जन-18	जन-19	जन-20	जन-21
खोले गए खातों की संख्या (करोड़ में)	6.84	3.72	3.1	3.68	3.76
जमा की गई राशि (रुपए लाख करोड़ में)	0.67	0.74	0.87	1.11	1.35

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
कार्यान्वयन में लीकेज रोकने के लिए 450 योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से जोड़ा गया।	▪ अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच 316 योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को डीबीटी कार्यक्रम के जरिए 2.94 लाख करोड़ रुपए संवितरित किए गए। सरकारी अनुमानों के अनुसार, इससे 1.78 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।[14]

तालिका 5: डीबीटी के जरिए वितरित राशि[14]

मानदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (जनवरी 2021 तक)
लाभार्थियों की संख्या (करोड़ में)	31.2	35.7	124	129.2	144.7	149
डीबीटी के जरिए वितरित राशि (करोड़ रुपए में)	61,492	74,689	1,90,871	2,32,105	3,81,631	2,95,546

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए रिकवर किए।	▪ इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 के अंतर्गत इनसॉल्वेंसी को हल करने की एक समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित की गई है। भारतीय इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ने कहा कि कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव ने उधारकर्ताओं पर बहुत अधिक वित्तीय दबाव बनाया है और कई कंपनियों की संभावित वायबिलिटी पर असर हुआ है।[15] इस संहिता में निम्नलिखित संशोधन किए गए: (i) मार्च 2020 और मार्च 2021 के बीच होने वाले डीफॉल्ट्स के लिए इनसॉल्वेंसी प्रक्रियाओं को शुरू करने से रोकना, और (ii) इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया को शुरू करने की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए करना।[16,17,18,19,20] ▪ जनवरी और सितंबर 2020 के बीच 4,008 मामलों को इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी प्रक्रिया के अंतर्गत दायर किया गया जिनमें से 1025 (26%) को लिक्विडेशन के आदेश और 277 (7%) को रेज़ोल्यूशन प्लान की मंजूरी के साथ समाप्त किया गया और 1,942 (49%) मामले अभी जारी हैं। 277 कॉरपोरेट ऋणदाताओं के एसेट्स का प्राप्य मूल्य 1.02 लाख करोड़ रुपए था जबकि उन पर 4.89 करोड़ रुपए बकाया था। रेज़ोल्यूशन से 1.97 लाख करोड़ रुपए रिकवर किए गए।

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	उद्योग
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2014 में 142 के स्थान पर 2020 में 63 हो गई है।	▪ अगस्त 2020 में विश्व बैंक ने वार्षिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को उन अनियमितताओं की खबरों के कारण रद्द कर दिया जिस पर जांच जारी है।[21] अक्टूबर 2019 में उसकी पिछली रिपोर्ट में 190 देशों में भारत की रैंकिंग 63 थी। भारत उन दस देशों में शामिल है जिनमें बिजनेस शुरू करने, निर्माण संबंधी परमिट हासिल करने, सीमा पार व्यापार करने और इनसॉल्वेंसी को हल करने से संबंधित सुधार हुए हैं। ▪ केंद्र सरकार ने 2018 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बिजनेस रिफॉर्म ऐक्शन प्लान (बीआरएपी) के अंतर्गत 180 सुधारों की सूची अधिसूचित की है जिन्हें 2019 तक लागू करना था।[22] बीआरएपी के अंतर्गत राज्यवार उपलब्धियों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। त्रिपुरा, सिक्किम और ओड़िशा का स्थान सबसे नीचे है।[23]
2015 से 2020 के बीच ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग्स में भारत 108 के स्थान पर 52वें स्थान पर पहुंचा। भारत में दिए गए पेटेंट्स की संख्या में इस अवधि के दौरान चार गुना बढ़ोतरी हुई। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में भी पांच गुना वृद्धि हुई।	▪ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में अपने वार्षिक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 48वां स्थान दिया है। इस रैंकिंग में राजनैतिक परिवेश, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे संकेतकों के आधार पर 131 देशों के इनोवेशंस का मूल्यांकन किया जाता है।[24] ▪ 2020-21 में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स ने 17,148 पेटेंट्स दिए और 1.35 लाख ट्रेडमार्क फाइल किए (नवंबर 2020 तक)। 2015-16 में जितने पेटेंट्स दिए गए थे, यह संख्या उससे 2.8 गुना अधिक है और फाइल किए गए ट्रेडमार्क्स से 3.2 गुना अधिक। **तालिका 6: 2015-16 और 2020-21 के दौरान फाइल पेटेंट्स (नवंबर 2020 तक)[25,26,25,26]**

मानदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (नवंबर 2020 तक)
फाइल पैंटेंट की संख्या	42,763	46,904	45,444	47,854	50,659	37,660
स्वीकृत पैंटेट की संख्या	5,978	6,326	9,847	13,045	15,283	17,148
स्वीकृत पेटेंट का %	**14%**	**13.5%**	**21.7%**	**27.3%**	**30.2%**	**45.5%**
फाइल ट्रेडमार्क्स की संख्या	2,10,501	2,83,060	2,78,170	2,72,974	3,23,798	2,78,023
रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स की संख्या	41,583	65,045	2,50,070	2,00,913	3,16,798	1,35,289
रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स का %	**19.8%**	**23%**	**90%**	**73.6%**	**97.8%**	**48.7%**

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td>भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है। स्टार्ट-अप इंडिया अभियान के अंतर्गत 27,000 स्टार्ट-अप्स को मान्यता दी गई है।</td><td>

योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स श्रम एवं पर्यावरणीय अनुपालनों के अंतर्गत सेल्फ सर्टिफिकेशन, सार्वजनिक खरीद संबंधी राहतों, बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े सहयोग तथा कर प्रोत्साहनों को हासिल करने के हकदार होते हैं।[27] सितंबर 2020 तक स्टार्ट-अप इंडिया अभियान के अंतर्गत सरकार ने 36,106 स्टार्ट-अप्स को मान्यता दी है (2016 में प्रारंभ से)। सरकार के अनुसार, अभियान के जरिए 4.2 लाख नौकरियों का सृजन हुआ है।[28]

तालिका 7: स्टार्ट-अप इंडिया अभियान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स[27,28]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020 (सितंबर तक)</th></tr>
<tr><td>मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स</td><td>503</td><td>5,444</td><td>8,918</td><td>11,754</td><td>36,106</td></tr>
<tr><td>नौकरियां (हजारों में)</td><td>-</td><td>49</td><td>95</td><td>156</td><td>422</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 5.5 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों ने ऋण लिए। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण योजना के अंतर्गत मंजूर किया गया।</td><td>

गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण देने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ऋण की तीन श्रेणियां हैं: (i) 'शिशु' (50 हजार रुपए से कम के ऋण), (ii) 'किशोर' (50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच के ऋण), और (iii) 'तरुण' (5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के बीच के ऋण)।[29]

तालिका 8: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण[29]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21 (जनवरी 2021 तक)</th></tr>
<tr><td>मंजूर ऋणों की संख्या (करोड़ में)</td><td>3.5</td><td>4.0</td><td>4.8</td><td>6.0</td><td>6.2</td><td>2.8</td></tr>
<tr><td>अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)</td><td>137</td><td>180</td><td>253</td><td>321</td><td>337</td><td>171</td></tr>
<tr><td>संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)</td><td>132</td><td>175</td><td>246</td><td>311</td><td>329</td><td>156</td></tr>
</table>

मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) की मदद के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत भी उपायों की घोषणा की, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉरपस के साथ फंड बनाना ताकि एमएसएमई को विकास क्षमता और वायबिलिटी के लिए इक्विटी फंडिंग मिले, (ii) एमएसएमईज़ को बैंकों और एनबीएफसीज़ से अपने संपूर्ण बकाया ऋण का 20% तक उधार लेने की अनुमति, जिसकी गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी, (iii) स्ट्रेस्ड एसेट्स वाले एमएसएमईज़ को इक्विटी के बदले ऋण देना, और (iv) सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एमएसएमईज़ पर बकाये भुगतान को 45 दिनों में जारी करना।[30,31,32,33]

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td>ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) की संख्या 2014 में 60,000 से बढ़कर 2019 में 3.65 लाख हुई। इन केंद्रों ने 12 लाख से अधिक गांवों में रोजगार प्रदान किया है।</td><td>
कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य पब्लिक यूटिलिटी सेवाओं, समाज कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय या शिक्षण सेवाओं के वितरण का एक्सेस प्वाइंट होता है। 2009 में सीएससी को शुरू किया गया था ताकि सुदूर क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर ई-सर्विसेज़ की डिलिवरी सुनिश्चित की जा सके, जहां इंटरनेट और कंप्यूटर पर्याप्त उपलब्ध नहीं हैं। अगस्त 2020 में भारत में 3.75 लाख से अधिक सीएससी संचालित हो रहे हैं।[34]
तालिका 9: 2016-17 और 2019-20 के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर सीएससीज़[35]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th></tr>
<tr><td>परिचालित सीएससीज़ की संख्या</td><td>2,12,934</td><td>2,63,890</td><td>3,45,246</td><td>3,65,361</td></tr>
<tr><td>परिचालित सीएससीज़ की संख्या में वृद्धि</td><td>17.0%</td><td>19.3%</td><td>23.6%</td><td>5.5%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>पांच औद्योगिक कॉरिडोर्स विकसित किए जाएंगे।</td><td>
औद्योगिक कॉरिडोर्स में उच्च गति वाले परिवहन, लॉजिस्टिक हब्स और टाउनशिप्स और नॉलेज पार्क जैसे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को एकीकृत करने का प्रयास किया जाता है।[36] तालिका 10 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित पांच औद्योगिक कॉरिडोर्स की प्रगति तथा केंद्र सरकार एवं एशियाई विकास बैंक (वाइजैग-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर के लिए) द्वारा धनराशि की मंजूरी एवं उन्हें जारी करने की स्थिति पर चर्चा है।
तालिका 10: औद्योगिक कॉरिडोर्स के निर्माण की प्रगति[36]
<table>
<tr><th rowspan="2">स्थान</th><th colspan="2">परियोजना राशि (करोड़ रुपए में)</th><th rowspan="2">प्रगति</th></tr>
<tr><th>मंजूर</th><th>जारी</th></tr>
<tr><td>वाइजैग-चेन्नई</td><td>1,500</td><td>-</td><td>एशियाई विकास बैंक के ऋण से कार्यान्वयन। चार नोड्स चिन्हित।</td></tr>
<tr><td>दिल्ली-मुंबई</td><td>620</td><td>579</td><td>479 एकड़ में 67 प्लॉट आबंटित। सभी चिन्हित नोड्स के लिए स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी मुख्य रूप से धनराशि जुटाने के लिए गठित बिजनेस एसोसिएशन है) निगमित।</td></tr>
<tr><td>अमृतसर-कोलकाता</td><td>14.7</td><td>10.8</td><td>परस्पेक्टिव प्लान (लंबे समय के विकास का ब्ल्यूप्रिंट) पूरा किया गया है। सात राज्यों में एकीकृत मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर साइट्स को अंतिम रूप दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>बेंगलुरू-मुंबई</td><td>4.1</td><td>4.1</td><td>परस्पेक्टिव प्लान पूरा किया गया है।</td></tr>
<tr><td>चेन्नई-बेंगलुरू</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>परस्पेक्टिव प्लान पूरा। चिन्हित तीन नोड्स में से दो के लिए एसपीवी निगमित।</td></tr>
</table>
नोट: आंकड़े नवंबर 2019 में अपडेट किए गए डेटा पर आधारित हैं।
</td></tr>
</table>

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग में तेज रफ्तार पकड़ रहा है। देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मूल्य बढ़ गया है और भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग हब बन गया है।	▪ तालिका 11 में 2014-15 के बीच भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मूल्य में वृद्धि की चर्चा की गई है।

तालिका 11: इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उत्पादन[37,38]

मानदंड	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भारत में बनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का मूल्य (करोड़ रुपए में)	1,90,366	2,43,263	3,17,331	3,88,306	4,58,006	5,46,550
वृद्धि दर (% में)	5.5%	27.8%	30.4%	22.4%	17.9%	19.3%

नोट: 2019-20 के डेटा अनंतिम अनुमानों पर आधारित हैं।

▪ भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग हब है। सरकार के अनुसार, 2014 से 2019 के बीच मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स की संख्या दो से बढ़कर 200 से अधिक हो गई और निर्मित हैंडसेट्स की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़ हो गई।[39]

▪ मार्च 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तीन योजनाओं को मंजूरी दी: (i) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन इनसेंटिव स्कीम (पीएलआई), (ii) संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम (ईएमसी 2.0), और (iii) स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स (एसपीईसीएस)। योजनाओं के दिशानिर्देश जून 2020 में जारी किए गए थे।[40,41,42] तीनों योजनाओं के जरिए 2025 तक 10 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।[42]

तालिका 12: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए घोषित योजनाएं[43,44,45,46]

योजना	लक्ष्य	आवेदनों की संख्या	योजना अवधि	आबंटन (करोड़ रुपए में)
पीएलआई	कंपोनेंट्स की घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग, एसेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकिंग यूनिट्स को प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्स देकर बढ़ावा देना।	22	5 वर्ष	40,995
ईएमसी 2.0	इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर्स और कॉमन फेसिलिटी सेंटर्स को लगाने के लिए वित्तीय सहायता देना ताकि तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित हो।	1	8 वर्ष	3,762
एसपीआईसी	टेलीकॉम उपकरण और मोबाइल, उपभोक्ता, एवं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सहित सेगमेंट्स की मैन्यूफैक्चरिंग के लिए 25% पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।	13	3 वर्ष	3,285

नोट: प्राप्त आवेदनों की संख्या से संबंधित डेटा सितंबर 2020 में अपडेट किए गए थे जब किसी मंजूरी को रिकॉर्ड नहीं किया गया था।[46]

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">रक्षा एवं गृह मामले</td></tr>
<tr><td>सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को गति दी जाएगी।</td><td>▪ सरकार ने सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण/आधुनिकीकरण के लिए 2020-21 में 90,048 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।[47] तालिका 13 में 2015-16 और 2020-21 के बीच आधुनिकीकरण हेतु बजटीय आबंटन और व्यय की प्रवृत्तियां प्रदर्शित की गई हैं।
तालिका 13: सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के बजट अनुमान और वास्तविक व्यय (करोड़ रुपए में)
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th></tr>
<tr><td>बजट अनुमान</td><td>77,406</td><td>69,898</td><td>69,473</td><td>74,115</td><td>80,959</td><td>90,047</td></tr>
<tr><td>वास्तविक व्यय</td><td>62,235</td><td>69,280</td><td>72,732</td><td>75,892</td><td>91,128</td><td>31,747</td></tr>
</table>
नोट: वास्तविक व्यय अनंतिम अनुमानों पर आधारित हैं। 2020-21 में वास्तविक व्यय को 31 जुलाई, 2020 को अपडेट किया गया था।
▪ रक्षा उत्पादन और खरीद संबंधी एस्टिमेट्स कमिटी (2018) ने कहा था कि रक्षा बजट में पूंजीगत खरीद का हिस्सा लगातार कम हो रहा है जिसका सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर प्रतिकूल असर हो रहा है। कमिटी ने सुझाव दिया था कि पूंजीगत बजट के पर्याप्त आबंटन का प्रावधान किया जाना चाहिए और धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए।[48]
▪ रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2019) ने कहा था कि प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अपर्याप्त आबंटन से अनुबंधीय बाध्यताओं में चूक हो सकती है। पिछले वर्ष के पूरे हुए अनुबंधों के संबंध में अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जो भुगतान अनुमानित होते हैं, वे प्रतिबद्ध देनदारियों में शामिल होते हैं। कमिटी ने सुझाव दिया था कि जिन आबंटनों का वादा किया गया है, उन्हें प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए संवितरित किया जाना चाहिए।[49]</td></tr>
<tr><td>दो रक्षा कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे।</td><td>▪ सरकार ने 2018-19 के बजट में घोषणा की थी कि वह उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा कॉरिडोर्स बनाएगी। रक्षा उत्पादन को बढ़ाने और मौजूदा रक्षा औद्योगिक इकाइयों के बीच कनेक्टिविटी देने के लिए इन कॉरिडोर्स में औद्योगिक बेस बनाया जाएगा।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>

तालिका 14 : प्रस्तावित रक्षा कॉरिडोर्स [50]

कॉरिडोर	चिन्हित नोड्स	घोषित निवेश (करोड़ रुपए में)
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ	3,700
तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबटूर, होसुर, सलेम और तिरुचिरापल्ली	3,100

नोट: दोनों कॉरिडोर्स की प्रगति का हालिया अपडेट नवबंर 2019 तक का है।

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, भारत 2020 में रक्षा उत्पादों और सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था।[51] रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2019) ने कहा था कि 2014-15 और 2018-19 के बीच विदेशी वेंडर्स से खरीद 39% से बढ़कर 48.7% हो गई।[49]
- एस्टिमेट्स कमिटी (2018) ने कहा कि मिलिट्री हार्डवेयर के लिए विदेशी आपूर्तियों पर निर्भरता ने आयात पर व्यय को बढ़ाया है लेकिन इससे राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर होती है, चूंकि आपात स्थितियों में ये आपूर्तियां हथियार प्रदान नहीं कर सकतीं। कमिटी ने सुझाव दिया था कि सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि आयात पर देश की निर्भरता कम हो।[48]
- स्वदेशी मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने और रक्षा उपकरणों की खरीद की समयावधि को कम करने के लिए सरकार ने सितंबर 2020 में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 को जारी किया। इसकी मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 'लीजिंग' को अधिग्रहण के एक तरीके के रूप में प्रस्तावित करना, प्रारंभिक पूंजीगत परिव्यय के स्थान पर आवर्ती रेंटल पेमेंट करना, (ii) पूंजीगत अधिग्रहण की श्रेणियों में 'खरीद' (ग्लोबल-भारत में मैन्यूफैक्चर) को जोड़ना, और (iii) ऐसे हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की सूची का प्रावधान, जिनका आयात प्रतिबंधित है।[52]

</td></tr>
<tr><td>नक्सलवाद का भौगोलिक प्रसार कम हो रहा है।</td><td>

- तालिका 15 में भारत में वामपंथ-चरमपंथ की घटनाओं और परिणामस्वरूप 2016 तथा 2020 के बीच मौतों की संख्या प्रदर्शित की गई है।

तालिका 15: 2016-19 के बीच वामपंथ-चरणपथ की घटनाएं (फरवरी 2020 तक)[53]

मानदंड	2016	2017	2018	2019	2020
घटनाएं	1,048	908	833	670	123
मारे गए सुरक्षा कर्मी	65	75	67	52	5

</td></tr>
</table>

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	कृषि एवं खाद्य आपूर्ति
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत आठ करोड़ से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक का आय समर्थन प्रदान किया गया।	▪ कृषि भूमि वाले किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए का आय समर्थन देने के लिए 2019 में पीएम-किसान योजना शुरू की गई। यह आय समर्थन 2,000 रुपए की तीन किश्तों में दिया जाता है। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 14.54 करोड़ लाभार्थियों की अपेक्षा की थी। 17 जनवरी, 2021 तक योजना के कुल लाभार्थी 11.52 करोड़ थे। 2020-21 में 10.7 करोड़ लाभार्थियों को पहली किश्त, 10.4 करोड़ को दूसरी और 9.7 करोड़ को तीसरी किश्त मिली।[54] 2020-21 में योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए जोकि मंत्रालय के कुल आबंटन का 53% था। 2019-20 में योजना के लिए बजटीय स्तर के आबंटन को 75,000 करोड़ रुपए से घटाकर संशोधित चरण में 54,370 करोड़ रुपए कर दिया गया।[55] ▪ कृषि संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2019-20) ने कहा कि योजना को लागू करने में कुछ दिक्कतें है जैसे: (i) अनेक राज्यों में उचित भू रिकॉर्ड उपलब्ध न होना, (ii) लाभार्थियों की पहचान और राज्यों द्वारा डेटा को अपलोड करने में देरी, (iii) पीएम-किसान डेटाबेस और आधार डेटा के बीच जनसांख्यिकी डेटा का मेल न होना, (iv) गलत बैंक खाते, और (v) ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्विटी के चलते डेटा अपलोड न होना। कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार को उन राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाना चाहिए जहां नामांकन की रफ्तार कम है और उचित कदम उठाए।[56]
खरीफ और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में नियमित वृद्धि।	▪ एमएसपी वह आश्वस्त मूल्य होता है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां केंद्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न खरीदती हैं। इस केंद्रीय पूल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनका बफर स्टॉक रखा जाता है। तालिका 16 में 2014-15 और 2020-21 के बीच विपणन मौसमों में धान और गेहूं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी को प्रदर्शित किया गया है।

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति

तालिका 16: धान और गेहूं की फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि (रुपए प्रति क्विंटल)[57]

मानदंड	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
धान (सामान्य) की एमएसपी	1,360	1,410	1,470	1,550	1,750	1,815	1,868
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का %	3.8%	3.7%	4.3%	5.4%	12.9%	3.7%	2.9%
गेहूं की एमएसपी	1,450	1,525	1,625	1,735	1,840	1,925	1,975
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का %	3.6%	5.2%	6.6%	6.8%	6.1%	4.6%	2.6%

- हालांकि हर वर्ष 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है, लेकिन सार्वजनिक खरीद कुछ ही फसलों तक सीमित है जैसे धान, गेहूं और कुछ हद तक दालों तक। तालिका 17 में 2019-20 में मुख्य फसलों के उत्पादन और खरीद को प्रदर्शित किया गया।

तालिका 17: 2019-20 में एमएसपी पर फसलों की खरीद (लाख मीट्रिक टन)[58]

मानदंड	चावल	गेहूं	दाल	मोटे अनाज	कुल
उत्पादन	1184	1076	231	454	2954
खरीद	511	390	28.4	4.3	934
कुल उत्पादन में खरीद का %	43.2%	36.2%	12.3%	0.9%	31.6%

- नीति आयोग की 2016 की रिपोर्ट में एमएसपी को लागू करने की समस्याओं का जिक्र था। इनमें निम्नलिखित शामिल है: (i) खरीद व्यापक रूप से कुछ ही राज्यों से की जाती है- उदाहरण के लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब देश का कुल 45% गेहूं उत्पादित करते हैं लेकिन वहां से 84.8% खरीद की जाती है, और पंजाब 26.5% धान का उत्पादन करता है लेकिन वहां से 42.3% खरीद की जाती है, (ii) किसानों को बुवाई के मौसम से पहले कम जानकारी होती है (नीति आयोग के अनुसार, 62% किसानों को बुवाई के मौसम के बाद एमएसपी की जानकारी मिलती है, (iii) खरीद केंद्रों तक लंबी दूरी, (iv) किसानों के लिए परिवहन की बढ़ती लागत, और (v) स्टोरेज की अपर्याप्त क्षमता। नीति आयोग ने कहा था कि किसानों को अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए कृषि मूल्य नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। किसानों को अक्सर संकट बिक्री, यानी एमएसपी से कम पर बिक्री करनी पड़ती है।[59]

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
400 नई मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजारों (ई-नाम) से जोड़ा गया ताकि उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सके।	▪ ई-नाम योजना मौजूदा एपीएमसी बाजारों को नेटवर्क करती है ताकि कृषि उत्पादों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाए जा सकें। इससे मुख्य रूप से व्यापार की लागत और सूचनाओं की विषमता कम होती है। 31 दिसंबर, 2020 तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 बाजार ई-नाम से एकीकृत हुए, जबकि 2019 में इनकी संख्या 421 थी। इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने वाले किसानों की संख्या 1.69 करोड़ और व्यापारियों की संख्या 1.53 लाख है। जनवरी 2021 तक इस प्लेटफॉर्म पर 1.15 लाख करोड़ मूल्य के कुल 3.94 करोड़ मीट्रिक टन का व्यापार हुआ।[60]
वन नेशन, वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) की शुरुआत।	▪ ओएनओआरसी पोर्टेबल राशन कार्ड्स और आधार आधारित सत्यापन के जरिए लाभार्थियों को खाद्यान्न अहर्ता की अखिल भारतीय उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। 29 दिसंबर, 2020 तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ओएनओआरसी योजना को लागू किया है। 69 करोड़ लाभार्थी इसके दायरे में आते हैं (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के अंतर्गत अहर्ता के लिए 86% पात्र आबादी)।[61] ▪ कोविड-19 के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव में मदद के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत वितरण के अतिरिक्त कई दूसरी योजनाएं भी शुरू की गई थीं। ओएनओआरसी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड्स से प्रवासी मजदूरों के लिए सबसिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त आसान हुआ। देशव्यापी लॉकडाउन के वक्त मई और जून में 2.8 करोड़ प्रवासियों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त मिले।[62]
श्रम	
विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 60 लाख किसानों, खेतिहर मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और व्यापारियों का कवरेज।	▪ 2019 में केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और व्यापारियों को 3,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन देने के लिए तीन योजनाएं शुरू कीं। सभी स्वैच्छिक और अंशदान आधारित योजनाएं है जिसकी पात्रता आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है। लाभार्थियों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच मासिक अंशदान देना होगा, जैसा निर्दिष्ट हो और सरकार भी उतना ही अंशदान देती है।[63,64,65] 3 जनवरी, 2021 तक तीनों योजनाओं के रजिस्टर्ड लाभार्थियों की संख्या 61.24 लाख है।[66]

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>तालिका 18: किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के लिए पेंशन योजनाएं (जनवरी, 2021 तक)[66]
<table>
<tr><th>योजना</th><th>लक्षित लाभार्थी</th><th>पात्रता</th><th>रजिस्टर्ड लाभार्थियों की संख्या</th></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना</td><td>असंगठित क्षेत्र के श्रमिक</td><td>15,000 प्रति माह से कम की आय</td><td>39,70,930</td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना</td><td>छोटे किसान</td><td>दो हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि</td><td>21,10,738</td></tr>
<tr><td>व्यापारियों और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना</td><td>दुकानदार, स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति और रीटेल व्यापारी</td><td>1.5 करोड़ रुपए से कम का जीएसटी टर्नओवर</td><td>43,183</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>श्रम संहिताओं को संहिताबद्ध किया जाएगा।</td><td>▪ सितंबर 2020 में संसद ने तीन संहिताओं को पारित किया जोकि इस प्रकार हैं: (i) व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य स्थितियों को रेगुलेट करने वाले 13 मौजूदा कानून सम्मिलित हैं, (ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 जोकि ट्रेड यूनियन्स, औद्योगिक विवादों और स्थायी आदेशों को रेगुलेट करने वाले तीन श्रम कानूनों का स्थान लेती है, और (iii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 जोकि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों का स्थान लेती है।[67,68,69]
▪ औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत ड्राफ्ट नियमों को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए अक्टूबर 2020 में जारी किया गया।[70] व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत ड्राफ्ट नियमों को नवंबर 2020 में जारी किया गया।[71,72]</td></tr>
<tr><td colspan="2">स्वास्थ्य</td></tr>
<tr><td>आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 27,000 से अधिक हेल्थ और वेलनेस केंद्र (एचडब्ल्यूसीज़)।</td><td>▪ योजना एचडब्ल्यूसीज़ की स्थापना करती है जोकि व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं और इनके दायरे में मातृत्व, बाल स्वास्थ्य सेवाएं तथा गैर संचारी रोग शामिल हैं। नवंबर 2020 तक 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50,025 एचडब्ल्यूसीज़ मौजूद हैं, जहां 28.1 करोड़ लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की हैं।[73] 2020-21 के बजट में योजना के लिए 1,600 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।[74]</td></tr>
</table>

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 75 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज।	▪ योजना गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती करने पर प्रति परिवार पांच लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। नवंबर 2020 तक इस योजना के अंतर्गत 1.4 करोड़ व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुए और इसके लिए 17,535 करोड़ रुपए अधिकृत किए गए। योजना के अंतर्गत 24,653 अस्पतालों को एम्पैनल किया गया है।[75] 2020-21 के केंद्रीय बजट में योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जिसमें 2019-20 के 3,200 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में शत प्रतिशत बढ़ोतरी है।[74]
6,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के जरिए गंभीर रोगों के लिए सस्ती दवाएं।	▪ प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के अंतर्गत जनौषधि केंद्रों में सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली जनेरिक दवाओं को सस्ती दरों पर बेचा जाता है ताकि स्वास्थ्य सेवा पर आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च कम किया जा सके।[76] अगस्त 2020 तक देश में 6,511 जनौषधि केंद्र चलाए जा रहे हैं।[77]
शिक्षा	
ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को मजबूती देने के लिए 'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम 2)' को शुरू किया गया।	▪ 2017 में स्वयम पोर्टल को शुरू किया गया जिसका लक्ष्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म्स के जरिए उत्तम शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाना है। जनवरी 2020 तक 2,800 से अधिक पाठ्यक्रमों को पेश किया गया और 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इसके अंतर्गत सर्टिफिकेट्स हासिल किए। पाठ्यक्रमों में 1.2 करोड़ विद्यार्थियों ने दाखिला लिया।[78] 2010-20 में 130 करोड़ रुपए की तुलना में 2020-21 के बजट में वर्चुअल क्लासरूम्स और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए 75 करोड़ रुपए आबंटित किए गए।[79] ▪ 30 जुलाई, 2020 को जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में समावेशी डिजिटल शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए: (i) ऑनलाइन क्लास के लिए इंटरफेस का विकास, (ii) कोर्सवर्क के लिए डिजिटल रेपोजिटरी बनाना, (iii) जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर न हो, वहां विविध भाषाओं में रेडियो और टीवी जैसे चैनलों का इस्तेमाल, (iv) वर्चुअल लैब्स बनाना, और (v) शिक्षकों को उच्च कोटि के ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स बनाने के लिए प्रशिक्षण।[80] ▪ स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सर्वे के जरिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के आधार पर पारिवारिक इकाइयों के वर्गीकरण का प्रावधान, (ii) डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>
और विशेष जरूरतों जैसे कारकों के आधार पर शिक्षकों द्वारा व्यापक योजना बनाना, और (iii) शिक्षकों के लिए हर दिन स्क्रीन टाइम और कुल ऑनलाइन गतिविधियों की सीमा तय करना।[81]

4.4% ग्रामीण पारिवारिक इकाइयों के पास कंप्यूटर (स्मार्टफोन के अतिरिक्त) है और लगभग 15% के पास इंटरनेट की सुविधा। शहरी पारिवारिक इकाइयों से 42% के पास इंटरनेट है। तालिका 19 में पारिवारिक इकाइयों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस और 5-14 वर्ष के बच्चों में उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता को स्पष्ट किया गया है।

तालिका 19: कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा और उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता (2017-18)[82]
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>कंप्यूटर वाली पारिवारिक इकाइयां</th><th>इंटरनेट सुविधा वाली पारिवारिक इकाइयां</th><th>5-14 वर्ष के बच्चों में कंप्यूटर इस्तेमाल करने की क्षमता</th><th>5-14 वर्ष के बच्चों में इंटरनेट इस्तेमाल करने की क्षमता</th></tr>
<tr><td>ग्रामीण</td><td>4.4%</td><td>14.9%</td><td>5.1%</td><td>5.1%</td></tr>
<tr><td>शहरी</td><td>23.4%</td><td>42.0%</td><td>21.3%</td><td>19.7%</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>10.7%</td><td>23.8%</td><td>9.1%</td><td>8.8%</td></tr>
</table>
नोट: कंप्यूटर में स्मार्टफोन शामिल नहीं है। कंप्यूटर का उपयोग करने की क्षमता का अर्थ है निम्नलिखित किसी भी कार्य में सक्षम होना जैसे: (i) फ़ाइल/फोल्डर को कॉपी या ट्रांसफर करना, (ii) ईमेल भेजना, (iii) कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को ट्रांसफर करना, इत्यादि। इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का अर्थ है कि वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम होना, ई-मेल या सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन का उपयोग करना।
</td></tr>
<tr><td>75 शिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (हेफा) के जरिए 37,000 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए गए।</td><td>

मुख्य शिक्षण संस्थानों में उच्च कोटि की अवसंरचना तैयार करने की जिम्मेदारी हेफा की है। सभी केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थान हेफा के सदस्य बन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हेफा को 10,000 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से केनरा बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रोत्साहित किया है।[83] 2022 तक उच्च शिक्षण संस्थानों की अवसंरचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए जुटाना हेफा की जिम्मेदारी है। 2020-21 के बजट में हेफा के लिए 2,200 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे जोकि 2019-20 के 2,100 करोड़ रुपए के आबंटन से अधिक हैं। जनवरी 2020 में हेफा द्वारा 25,564 करोड़ रुपए मंजूर किए गए जिसमें से 5,537 करोड़ रुपए 75 शिक्षण संस्थानों को संवितरित किए गए।[84]

</td></tr>
</table>

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक मामले
6.6 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों की सदस्य बनीं जोकि निम्न ब्याज दरों पर ऋण मुहैय्या कराते हैं।	▪ राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन का लक्ष्य गरीबी कम करना है। इसके लिए जीविकोपार्जन में सुधार तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर पारिवारिक आय में वृद्धि की जाती है। मिशन की आजीविका योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूहों की स्थापना का प्रयास किया गया है।[85] 2020-21 में मिशन के लिए 9,210 करोड़ रुपए आबंटित किए गए जोकि 2019-20 में 9,024 करोड़ रुपए के आबंटन से अधिक हैं।[86] जनवरी 2021 तक योजना के अंतर्गत 66.7 लाख स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं जिनके 7.3 करोड़ सदस्य हैं।[87]
मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 3.5 करोड़ शिशुओं और 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।	▪ मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य निम्न टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों में टीकाकरण रहित और आंशिक टीकाकरण वाले बच्चों को कवर करना है। इसमें बच्चों के लिए 12 रोगों के टीके हैं। योजना के अंतर्गत फरवरी 2020 तक 3.6 करोड़ बच्चों और 91.4 लाख गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए।[88]
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1.2 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 5,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए।	▪ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है जोकि गर्भवती एवं शिशु को स्तनपान करने वाली महिलाओं को वेतन के नुकसान का मुआवजा देती हैं। योजना यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि महिलाओं को प्रसव से पहले और उसके बाद (पहले जीवित बच्चे के लिए) पर्याप्त आराम मिले और वह उचित पोषण से वंचित न हो।[89] योजना के अंतर्गत पहले बच्चे के जन्म पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए तीन किश्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं। 2020-21 में योजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए जिसमें 2019-20 में 2,300 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले वृद्धि है।[86] जनवरी 2020 तक 1.2 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 5,300 करोड़ रुपए के मातृत्व लाभ जमा कराए गए।[90]
महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इनमें 600 से अधिक वन-स्टॉप सेंटर्स, 1000 फास्ट ट्रैक विशेष अदालत तथा हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्पडेस्क लगाने का प्रस्ताव है।	▪ **वन स्टॉप सेंटर**: इन्हें 2015 में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया था ताकि हिंसा प्रभावित महिलाओं की मदद की जा सके। इन सेंटर्स में शेल्टर के अलावा पुलिस, मेडिकल, कानूनी तथा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। सितंबर 2020 तक 733 सेंटर्स को मंजूरी दी गई थी जिनमें से 684 काम कर रहे थे।[91] ▪ **फास्ट ट्रैक अदालत**: 2019 में विधि विभाग ने 1,023 अदालतों की स्थापना की मांग की है जिसमें बलात्कार के लंबित मामलों के फास्ट ट्रायल और निपटारे के लिए 634 फास्ट ट्रैक अदालतें और बच्चों के यौन शोषण के मामलों के लिए 389

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>विशेष अदालतें शामिल हैं।[92] दिसंबर 2020 तक 597 फास्ट ट्रैक अदालतों और बच्चों के यौन शोषण के मामलों की सुनवाई करने वाली 321 विशेष अदालतों सहित 918 अदालतें काम कर रही थीं।[93]
▪ महिला हेल्पडेस्क: इन हेल्पडेस्क की प्रमुख महिला पुलिस अधिकारी होती हैं और इनमें काम करने वाले अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।[94] 2020-21 में 10,000 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्पडेस्क बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे।[95]</td></tr>
<tr><td colspan="2">संसदीय एवं प्रशासनिक मामले</td></tr>
<tr><td>17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पिछले सात दशकों के प्रदर्शनों का नया रिकॉर्ड बनाया गया।</td><td>▪ 2020 के बजट सत्र के 175 दिन बाद 2020 का मानसून सत्र आयोजित किया गया जोकि जनवरी 2021 तक दो सत्रों के बीच सबसे बड़ा अंतराल है, वह भी बिना आम चुनाव हुए। संविधान में दो सत्रों के बीच छह महीने की सीमा निर्धारित की गई है और यह अंतराल उससे छह दिन कम था। लोकसभा में उपाध्यक्ष पद का चुनाव पहले सत्र के शुरू होने के 464 दिन तक नहीं हुआ। बिना उपाध्यक्ष के लोकसभा की यह सबसे लंबी अवधि है। मानसून सत्र 2020 के दौरान प्रश्नकाल नहीं हुआ जोकि इससे पहले केवल 1971 के युद्ध और आपातकाल के दौरान संचालित नहीं किया गया था।[96] 2020 वह साल रहा जब किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान सबसे कम दिन संसद की बैठक हुई (33 दिन), चूंकि शीतकालीन सत्र संचालित नहीं किया गया था।
▪ तालिका 20 में 17वीं लोकसभा के प्रदर्शन को स्पष्ट किया गया है। 2019 बजट सत्र के दौरान 40 बिल्स पेश किए गए थे जिनमें से उसी सत्र के दौरान 30 बिल्स पारित किए गए। पिछले 10 वर्षों में किसी सत्र में यह सर्वाधिक है।[97]
तालिका 20: 17वीं लोकसभा में संसद का प्रदर्शन[98]
<table>
<tr><th>सत्र</th><th>बजट 2019</th><th>शीतकाल 2019</th><th>बजट 2020</th><th>मानसून 2020</th></tr>
<tr><td>पेश किए गए बिल</td><td>40</td><td>18</td><td>19</td><td>22</td></tr>
<tr><td>पारित किए गए बिल</td><td>30</td><td>15</td><td>12</td><td>27</td></tr>
<tr><td>कमिटी को भेजे गए बिल</td><td>2</td><td>7</td><td>0</td><td>2</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ट्रिब्यूनल प्रणाली में सुधार किया गया।</td><td>▪ फरवरी 2020 में ट्रिब्यूनल, अपीलीय ट्रिब्यूनल और अन्य अथॉरिटीज़ (सदस्यों की क्वालिफिकेशन, अनुभव और सेवा शर्त) नियम, 2020 को अधिसूचित किया गया। नियम 19 ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों की क्वालिफिकेशन, अनुभव और सेवा शर्तों को स्थापित करते हैं।[99] नवंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इनके नियमों से संबंधित कई पहलुओं पर फैसला दिया था।[100]</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>▪ फैसले की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं: (i) केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल्स में नियुक्तियों और उनके कामकाज पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाना चाहिए, (ii) 10 वर्ष के अनुभव वाले वकील ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, (iii) ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल चार के बजाय, पांच वर्ष होगा, और (iv) सिलेक्शन कमिटी के सुझावों के तीन महीने के भीतर केंद्र सरकार सभी ट्रिब्यूनल्स के लिए नियुक्तियां करेगी।[100]</td></tr>
<tr><td colspan="2">परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर</td></tr>
<tr><td>अगले पांच वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे।</td><td>▪ वित्त मंत्री ने अपने 2019-20 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स पर अगले पांच वर्षों के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। प्रस्तावित प्रॉजेक्ट्स पर राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) बनाने के लिए 2020 की टास्क फोर्स ने 2019-20 से 2020-25 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 111 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया है। इसमें से 79% सरकार (39% केंद्र और 40% राज्य) तथा शेष 21% निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। 83-85% एनआईपी को सीधे आबंटन, ऋण, निजी डेवलपर्स की इक्विटी, बाहरी सहायता और पीएसयूज़ के आंतरिक एक्रुअल से जुटाया जाएगा।[101] जनवरी 2021 तक 131 लाख करोड़ रुपए के 7,410 प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 1,742 प्रॉजेक्ट्स चालू हैं।[102] तालिका 21 में एनआईपी के अंतर्गत क्षेत्रवार प्रगति प्रदर्शित की गई है।
तालिका 21: राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत प्रॉजेक्ट्स (जनवरी 2021 तक) (लाख करोड़ रुपए में)[103]
<table>
<tr><th>विशेष</th><th>परिवहन</th><th>ऊर्जा</th><th>जल और सैनिटेशन</th><th>सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर</th><th>कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर</th><th>लॉजिस्टिक्स</th><th>संचार</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>प्रॉजेक्ट्स की संख्या</td><td>3,646</td><td>519</td><td>1,330</td><td>1,094</td><td>627</td><td>155</td><td>39</td><td>7,410</td></tr>
<tr><td>प्रॉजेक्ट की लागत (लाख करोड़ रुपए में)</td><td>54.4</td><td>29.8</td><td>20.8</td><td>16.8</td><td>5.9</td><td>2.7</td><td>0.8</td><td>131</td></tr>
<tr><td>कुल प्रॉजेक्ट्स का %</td><td>49.2%</td><td>17.9%</td><td>14.8%</td><td>8.5%</td><td>7%</td><td>2.1%</td><td>0.5%</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्हें अपग्रेड किया जाएगा।</td><td>▪ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी सभी पात्र बसाटहों को बारहमासी सड़कें प्रदान करना है। योजना के लिए 2020-21 में 19,500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जोकि 2019-20 में 19,000 करोड़ रुपए के आबंटन से अधिक है।[123] ग्रामीण लिक्स और मार्गों के जरिए 1.2 लाख किलोमीटर सड़कों के एकीकरण के लिए एमजीएसवाई के तीसरे चरण को 2019 में शुरू किया गया था।[104]</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>
तालिका 22: पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रगति (किलोमीटर में)[105]
<table>
<tr><th>अवधि</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21 (जनवरी 2021 तक)</th></tr>
<tr><td>सड़क (लक्ष्य)</td><td>33,649</td><td>48,812</td><td>51,000</td><td>57,700</td><td>50,097</td><td>66,784</td></tr>
<tr><td>सड़क (काम पूरा हुआ)</td><td>35,155</td><td>47,446</td><td>48,746</td><td>16,856</td><td>27,301</td><td>15,336</td></tr>
<tr><td>प्राप्त लक्ष्य %</td><td>104.5%</td><td>97.2%</td><td>95.6%</td><td>29.2%</td><td>54.5%</td><td>23%</td></tr>
</table>
ग्रामीण विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2018-19) ने कहा कि योजना के अंतर्गत काम की रफ्तार बहुत धीमी है, खासकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में। कमिटी ने सुझाव दिया था कि योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रॉजेक्ट्स की गति को बढ़ाया जाए।[106]
</td></tr>
<tr><td>2019 में उड़ान योजना के अंतर्गत 335 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई और 35 लाख लोगों ने हवाई यात्राएं कीं।</td><td>2016 में उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) को शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य सस्ती कीमतों पर क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना था। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस)-उड़ान के अंतर्गत नए मार्गों को मंजूरी मिली है।[107] जुलाई 2020 तक योजना के अंतर्गत 766 मार्गों को मंजूरी मिली है जिनमें से 274 चालू हैं।[108] अगस्त-अक्टूबर 2020 के बीच 84 नए मार्गों को मंजूरी दी गई।[109,110,111] दिसंबर 2019 तक योजना के अंतर्गत 34.7 लाख यात्रियों ने हवाई यात्राएं कीं।[112] देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान हवाई यात्रा रोक दी गई थी और कोविड-19 महामारी के कारण कुछ चुनौतियां भी पेश आईं, जिनमें कम यात्री, निश्चित सीमा तक किराया और कुछ मार्गों पर लंबे समय तक प्रतिबंध शामिल हैं।[113,114,115]</td></tr>
<tr><td colspan="2">शहरी एवं ग्रामीण विकास</td></tr>
<tr><td>रुके हुए हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई।</td><td>2019 में स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग (स्वामिह निवेश फंड) स्थापित किया गया था जिसका लक्ष्य सस्ते और मध्यम आय वर्ग वाले आवासीय क्षेत्र में रुके हुए हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स जिनका निवल मूल्य पॉजिटिव है, की सहायता करना है।[116] ऐसे 1,509 हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स हैं जिनमें 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट्स हैं और वे रुकी हुई श्रेणी में आते हैं। रुके हुए 90% प्रॉजेक्ट्स सस्ते और मध्यम आय वर्ग वाले सेगमेंट का हिस्सा हैं।[117]
केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए लगाने, और बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे योगदानकर्ताओं से 15,000 करोड़ रुपए जमा करने का प्रस्ताव रखा है। एसबीआई तथा एचडीएफसी सहित 14 निवेशकों ने पहले चरण में योगदान दिया</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>है और 10,530 करोड़ रुपए का डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया है।[118] 1 दिसंबर, 2020 तक 135 प्रॉजेक्ट्स के लिए 13,191 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। इससे 86,777 हाउसिंग यूनिट्स को लाभ मिलने की उम्मीद है।[119]</td></tr>
<tr><td>दो करोड़ गरीब लोगों के लिए घर।</td><td>▪ 2022 तक सभी के लिए आवास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को शुरू किया गया था। इसके दो घटक हैं- पीएमएवाई-शहरी और पीएमएवाई-ग्रामीण।
तालिका 23: कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे हुए मकान (करोड़ में)[120,121]
<table>
<tr><th>पीएमएवाई</th><th>मंजूर मकान</th><th>पूरे हुए मकान</th><th>पूरे हुए मकानों का प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>ग्रामीण</td><td>1.87</td><td>1.26</td><td>67.1%</td></tr>
<tr><td>शहरी</td><td>1.09</td><td>0.41</td><td>37.8%</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>2.96</td><td>1.67</td><td>52.5%</td></tr>
</table>
नोट: यह सूचना 18 जनवरी, 2021 को अपडेट की गई है।
▪ 2020-21 में शहरी घटक के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया। यह 2019-20 के संशोधित अनुमान से 17% अधिक है।[122] ग्रामीण आवास के लिए 2020-21 में 19,500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था जिसमें 2019-20 में 19,000 करोड़ रुपए की तुलना में वृद्धि है।[123] नवंबर 2020 में 12 लाख मकानों की ग्राउंडिंग और 18 लाख मकानों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई (शहरी) योजना को अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए।
▪ पीएमएवाई (शहरी) योजना के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग (6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच वार्षिक आय) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम 2017 से प्रारंभ है। यह मकानों के अधिग्रहण, निर्माण या उन्हें बढ़ाने के लिए पात्र शहरी गरीबों या मध्यम आय वर्ग के समूह को होम लोन्स पर अनुदान देने का प्रयास करती है। सरकार का अनुमान है कि हाउसिंग क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2.5 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा।[124] जनवरी 2017 से नवंबर 2019 के बीच इस योजना से 2.3 लाख परिवार लाभान्वित हुए।[125]</td></tr>
<tr><td>ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया।</td><td>▪ 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, तब भारत के 38.7% जिले खुले में शौच मुक्त थे।[126] अक्टूबर 2020 में 100% जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। जनवरी 2021 तक मिशन के अंतर्गत 10.74 करोड़ पारिवारिक इकाइयों में शौचालय बनाए जा चुके हैं और 16.4 करोड़ पारिवारिक इकाइयों में शौचालय है।[126]</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>▪ ग्रामीण विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2018) ने कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया था, जैसे (i) 100% पारिवारिक इकाई शौचालय वाले गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित नहीं किया जा सकता, जब तक कि सारे निवासी उन्हें इस्तेमाल नहीं करते, (ii) शौचालयों को खराब क्वालिटी के कच्चे माल से और पानी की उपलब्धता के बिना बनाया गया है, और (iii) शौचालयों की गलत सूचना देने तथा उनके सस्टेनेबल न होने के कारण ओडीएफ घोषित गांवों की फॉल बैक (फिर से खुले में शौच की प्रवृत्ति) दर काफी उच्च है।[127]</td></tr>
<tr><td colspan="2">ऊर्जा</td></tr>
<tr><td>भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, यहां एलपीजी कवरेज 55% से बढ़कर 97% हो गया है।</td><td>▪ तालिका 24 में 2015 और 2020 के बीच भारत में एलपीजी कवरेज और अन्य मुख्य संकेतकों पर चर्चा की गई है।
तालिका 24: 2015 और 2020 के बीच भारत में एलपीजी कवरेज पर मुख्य संकेतक[128]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>अप्रैल 2015</th><th>अप्रैल 2016</th><th>अप्रैल 2017</th><th>अप्रैल 2018</th><th>अप्रैल 2019</th><th>अप्रैल 2020</th><th>दिसंबर 2020</th></tr>
<tr><td>एलपीजी कवरेज (% क्षेत्र)</td><td>56.2%</td><td>62%</td><td>72.8%</td><td>80.9%</td><td>94.3%</td><td>97.5%</td><td>99.3%</td></tr>
<tr><td>एलपीजी वितरकों की संख्या</td><td>15,930</td><td>17,916</td><td>18,786</td><td>20,146</td><td>23,737</td><td>24,670</td><td>24,782</td></tr>
<tr><td>एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स की संख्या</td><td>187</td><td>188</td><td>189</td><td>190</td><td>192</td><td>196</td><td>198</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>आठ करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं।</td><td>▪ मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन (बीपीएल) करने वाले परिवार की महिलाओं को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) देना है। 2020 में 9,700 करोड़ रुपए मूल्य के 11.9 करोड़ से अधिक सिलिंडर बुक और डिलिवर किए गए (जून 2020 तक के आंकड़े)।[129]
▪ योजना पर कैग की 2019 की एक रिपोर्ट में निम्नलिखित निष्कर्ष दिए गए थे: (i) 2016-19 में भारत में एलपीजी कवरेज 62% से बढ़कर 94% होगया लेकिन औसत वार्षिक रीफिल उपभोग कम बना रहा, जोकि लाभार्थियों के कम इस्तेमाल का संकेत देता है, (ii) विवरण देने के सात दिनों के भीतर केवल 19% कनेक्शंस लगाए गए जोकि इंस्टॉलेशन में देरी का संकेत है, (iii) अधिक उपभोग वाले मामलों में घरेलू सिलिंडर के कमर्शियल इस्तेमाल का जोखिम है, और (iv) योजना के प्रदर्शन संकेतकों का अभाव है।[130]</td></tr>
</table>

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
पूर्वोत्तर गैस ग्रिड प्रॉजेक्ट के लिए 9,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।	▪ इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा यह प्रॉजेक्ट चलाया जा रहा है जोकि केंद्रीय-सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उद्यमों का संयुक्त उपक्रम है। 9,265 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के 60% की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) को जनवरी, 2019 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।[131] वीजीएफ पूर्ण निजी निवेश के लिए अनाकर्षक माने जाने वाले प्रॉजेक्ट्स के लिए एकमुश्त पूंजीगत अनुदान देता है। दिसंबर, 2020 तक कुल प्रस्तावित 1,656 किमी में से 1,544 किमी पाइपलाइन डाल दी गई है।[132]
2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।	▪ सार्वभौमिक बिजलीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) को शुरू किया गया था। अक्टूबर 2019 और नवंबर 2020 के बीच योजना के अंतर्गत 2.8 करोड़ परिवारों को बिजली दी गई। 2020-21 में इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 6,220 करोड़ रुपए जारी किए।[133] ▪ ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि कोविड-19 और उसके बाद लॉकडाउन से बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत डिस्कॉम्स, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक कंपनियों और ग्रामीण बिजलीकरण एवं बिजली वित्तीय निगमों को सहायता दी गई है ताकि बिजली क्षेत्र में लिक्विडिटी सुनिश्चित की जा सके।
भारत 2030 तक 450 गिगावॉट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करेगा।	▪ 2019 में ऊर्जा मंत्रालय ने यह लक्ष्य रखा कि 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 450 गिगावॉट किया जाएगा। दिसंबर 2020 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 221 गिगावॉट है (लक्ष्य का 49%)[134] जनवरी 2021 तक अक्षय ऊर्जा देश की स्थापित ऊर्जा क्षमता का 24% और इलेक्ट्रिकल ऊर्जा उत्पादन क्षमता का 11% है।[135]

तालिका 25: दिसंबर 2020 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता (गिगावॉट में)[134]

मानदंड	सौर ऊर्जा	जल	वायु	जैव ऊर्जा	राउंड द क्लॉक ऊर्जा	वायु सौर हाइब्रिड	कुल
स्थापित क्षमता	36.32	49.7	38.26	10.31	0	0	134.6
कार्यान्वयन में	37.1	13.4	8.99	0	1.6	1.44	62.5
टेंडर दिए गए	21.21	-	-	-	5	1.2	27
कुल	94.63	63.2	47.25	10.31	6.6	2.64	221

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के	▪ मार्च 2019 में कृषि पंप्स के सौरीकरण के लिए पीएम-कुसुम को शुरू किया गया था।[136] इस योजना का लक्ष्य 2017 और 2022 के बीच केंद्र सरकार की 34,035 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता के साथ सौर और अन्य अक्षय ऊर्जा क्षमता को

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
अंतर्गत किसानों को 17 लाख सौर पंप्स दिए जाएंगे।	जोड़ना है। 2020 में योजना के अंतर्गत लक्ष्य को 17.5 लाख पंप (25.8 गिगावॉट बिजली उत्पादित करने वाले) लगाने से बढ़ाकर 20 लाख पंप (30.8 गिगावॉट बिजली उत्पादित करने) किया गया है।[137] ▪ 2020-21 में 5,000 छोटे सौर ऊर्जा पंप, 7 लाख स्टैंडएलोन सौर पंप और 4 लाख ग्रिड कनेक्टेड पंप के सौरीकरण का लक्ष्य था।[134] 2019-20 में नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने छोटे ऊर्जा संयंत्रों द्वारा 1000 छोटे संयंत्रों, 1.7 लाख स्टैंडएलोन सौर जल पंप और 69,008 ग्रिड कनेक्टेड पंप्स के सौरीकरण को मंजूरी दी।
जल एवं पर्यावरण	
जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार में पर्याप्त मात्रा में पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।	▪ 2019 में जल जीवन मिशन को शुरू किया गया था ताकि 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को चालू नल कनेक्शन दिया जा सके। जनवरी 2021 में 91,121 परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए (ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या का 0.04%)। 5 जनवरी, 2021 तक 6.4 करोड़ परिवारों के पास नल कनेक्शन था।[138] 2020-21 में योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया जोकि 2019-20 के संशोधित अनुमान (10,001 करोड़ रुपए) से अधिक है।[139]
नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 7.2 लाख करोड़ रुपए की लागत के प्रॉजेक्ट्स पूरे किए गए।	▪ मिशन की शुरुआत गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुत्थान के लक्ष्य से की गई थी। इन कार्यों में म्यूनिसिपल सीवेज और औद्योगिक उत्सर्जनों का उपचार, नदी की सतह की सफाई, ग्रामीण सैनिटेशन और वनीकरण शामिल हैं।[140] 2014-15 और 2019-20 के दौरान मिशन को लागू करने के लिए 12,324 करोड़ रुपए आबंटित किए गए।[141,142] सितंबर 2020 तक 28,854 करोड़ रुपए की लागत से 315 प्रॉजेक्ट्स मंजूर किए गए जिनमें से 132 प्रॉजेक्ट्स पूरे हो गए हैं।[141] ▪ जल संसाधन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2017-18) ने कहा था कि योजना की भौतिक प्रगति संतोषजनक नहीं है।[143] कमिटी के निष्कर्षों के जवाब में मंत्रालय ने कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया था, जैसे (i) टेंडरिंग की प्रक्रिया में देरी, (ii) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए जमीन उपलब्ध न होना जिसके कारण प्रॉजेक्ट्स के निष्पादन में देरी होती है, (iii) शहरों में घरों में पर्याप्त सीवेज कनेक्शन न होने के कारण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता का पूरा उपयोग न होना, और (iv) पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स और सामुदायिक सलाह को पूरी तरह से लागू न करना, इत्यादि।[144]

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
वायु प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए 102 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छव वायु कार्यक्रम को लागू किया गया है।	▪ जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को शुरू किया गया था ताकि 2024 तक $PM_{2.5}$ और PM_{10} प्रदूषकों को कम करने (2017 के स्तर की तुलना में) के राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सके।[145] कार्यक्रम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उन शहरों को चिन्हित करने की शक्ति देता है जो अधिसूचित राष्ट्रीय एंबियंट एयर क्वालिटी मानक का अनुपालन नहीं करते। सीपीसीबी ने 2014-18 में वायु की गुणवत्ता के आधार पर 122 शहरों को चिन्हित किया।[146] 2019-20 के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स ने 225 करोड़ रुपए जारी किए हैं।[147] 2020-21 में कार्यक्रम को वित्त पोषित करने के अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स और कमिटियों को वित्तीय सहायता के जरिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए 460 करोड़ रुपए आबंटित किए गए।[148] ▪ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश, 2020 को अक्टूबर 2020 में जारी किया गया। अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के लिए बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने और उनका हल करने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है।[149] ▪ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में जारी एक पेपर में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य संबंधी तथा आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की गई है। इसके मुख्य निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 2019 में 17 लाख मौतों के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है (कुल मौतों का 18%), (ii) समय पूर्व मौतों और बीमारियों के कारण कम उत्पादन से होने वाली आर्थिक हानि जीडीपी का 1.4% है जोकि 2.6 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, और (iii) 1990 और 2019 के बीच वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु दर में 115% की वृद्धि हुई।
विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी	
भारतनेट योजना के अंतर्गत 1.25 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को उच्च रफ्तार वाले ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है।	▪ 2011 में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को कनेक्टिविटी देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। जनवरी 2021 तक 4.89 लाख किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाकर 1.63 लाख जीपी को जोड़ा गया है। इनमें से 1.5 लाख जीपी सेटेलाइट मीडिया पर सर्विस के लिए तैयार हैं।[150,151]

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
डेटा प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 को संसद में पेश किया गया।	▪ दिसंबर 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह व्यक्तियों के पर्सनल डेटा को संरक्षित रखने तथा इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की स्थापना का प्रयास करता है।[152] बिल को दिसंबर 2019 में ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमिटी को भेजा गया था। कमिटी की रिपोर्ट संसद में पेश होनी है।[153]
चंद्रयान-3 प्रॉजेक्ट को मंजूरी दी गई है।	▪ चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित तीसरा चंद्र अभियान होगा। यह लॉन्च 2021 की पहली छमाही के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्षमता और डिजाइन के लिहाज से चंद्रयान-2 के आधार पर परिष्कृत की गई है।[154]
इसरो एक मानवयुक्त अंतरिक्ष यान कार्यक्रम, गगनयान पर काम कर रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले दो मानवरहित मिशन लॉन्च किए जाएंगे।	▪ कार्यक्रम के लिए 9,023 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। कार्यक्रम की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए के भीतर होने का अनुमान है, जिसमें प्रौद्योगिकी विकास, फ्लाइट हार्डवेयर रियलाइजेशन और बुनियादी ढांचे को विकसित करने की लागत शामिल है। चार लोगों को अंतरिक्ष उड़ान का प्रशिक्षण देने और डिजाइन, विकास और वितरण पर राष्ट्रीय सहयोग का काम शुरू हो गया है। मानव रहित मिशनों के लिए शैक्षणिक संस्थानों से चार जैविक और दो भौतिक विज्ञान संबंधी प्रयोगों को सूचीबद्ध किया गया है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

1. Address by the President of India to the Joint Sitting of two houses of Parliament, Office of the President of India, January, 2020, https://presidentofindia.nic.in/speeches-detail.htm?798.
2. GDP: current prices, International Monetary Fund data mapper, last accessed on December 22, 2020, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.
3. India: at a glance, International Monetary Fund, last accessed on January 18, 2020, https://www.imf.org/en/Countries/IND.
4. Provisional Estimates of Annual Income, 2019-20, Ministry of Statistics and Programme Implementation, May 29, 2020, https://www.mospi.gov.in/documents/213904/416359//PRESS%20NOTE%20PE%20and%20Q4%20estimates%20of%20GDP1600850161778.pdf/661ea24e-9ac7-1444-94f2-be87f79d773e.
5. Provisional Estimates of Annual Income, 2017-18, Ministry of Statistics and Programme Implementation, May 31, 2020, https://mospi.gov.in/documents/213904/416359//nad_PR_31may181600867734516.pdf/82e0ad2d-87e2-5942-3174-acd7ab7b8f5c.
6. Press Note on First Advance Estimates of National Income 2020-21, Press Information Bureau, Ministry of Finance, January 7, 2020, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Presss%20note%20for%20FAE-2020-21.pdf.
7. Factsheet on Foreign Direct Investment, April, 2000 to September 2020, https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI_Fact_sheet_September_20.pdf.
8. Factsheet on Foreign Direct Investment, April, 2000 to September 2019, https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI_Factsheet_September2019_01January2019.pdf.

9. Factsheet on Foreign Direct Investment, April, 2000 to September 2018, https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI_FactSheet_1February2019.pdf.
10. RBI Database, last accessed on January 18, 2020, https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=home.
11. "India's Foreign Trade Data: December, 2020", Ministry of Commerce and Industry, Press Information Bureau, January 15, 2021.
12. Unique Identification Authority of India, State/UT wise Aadhaar saturation, last accessed on January 18, 2021, https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/india.php.
13. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Archive, last accessed on January 18, 2020, https://www.pmjdy.gov.in/Archive.
14. Direct Benefit Transfer, Government of India, last accessed January 18, 2021, https://dbtbharat.gov.in/.
15. Quarterly Newsletter (July-September, 2020), Insolvency and Bankruptcy Board of India, September, 2020, https://ibbi.gov.in/uploads/publication/411436dab58c1265aacb015b6b43a215.pdf.
16. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020, Ministry of Corporate Affairs, 2020, http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/IBCAmedBill_05062020.pdf.
17. S.O. 4638(E), Ministry of Corporate Affaits, December 22, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/223855.pdf.
18. S.O. 3265 (E), Ministry of Corporate Affairs, September 24, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/221936.pdf.
19. S.O. 1205(E), Gazette of India, Ministry of Corporate Affairs, March 24, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/218898.pdf.
20. The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Act, 2020, Ministry of Corporate Affairs, September 23, 2020, http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/IBCAmedBill_24092020.pdf.
21. Doing Business – Data Irregularities Statement, The World Bank, August 27, 2020, https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/08/27/doing-business---data-irregularities-statement.
22. State Business Reform Action Plan -2019 Implementation Guide for States/UTs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, February 2019, https://dipp.gov.in/sites/default/files/Implementation_Guide_2019_dated_04022019.pdf
23. "Ranking of states based on implementation of Business Reform Action Plan for the year 2019 declared", Ministry of Commerce & Industry, Press Information Bureau, September 5, 2020.
24. Global Innovation Index, 2020, World Intellectual Property Organisation, 2020, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf.
25. Annual Report, The Office Of The Controller General Of Patents, Designs, Trade Marks And Geographical Indications, Ministry of Commerce and Industry, 2019, https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/IP_India_Annual_Report_2019_Eng.pdf.
26. Year End Review- 2020 for Department for Promotion of Industry & Internal Trade, Press Information Bureau, Ministry of Commerce and Industry, December 31, 2020, https://www.pib.nic.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1685013.
27. Evolution of Start-up India: Capturing the four year story, Ministry of Commerce and Industry, February, 2020, https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/Templates/public/4_years_Achievement_report_v21%20_%20%2022%20Dec%202020%20V1.pdf.
28. Lok Sabha Unstarred Question No. 564, Ministry of Commerce and Industry, September 16, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/174/AU564.pdf.
29. Pradhan Mantri MUDRA Yojana, last accessed on January 18, 2021, https://www.mudra.org.in/
30. Atmanirbhar Presentation Part-1 Business including MSMEs, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, May 20, 2020, https://msme.gov.in/sites/default/files/AtmanirbharPresentationPart-1BusinessincludingMSMEs13-5-2020_0.pdf.
31. "Cabinet approves additional funding of up to Rupees three lakh crore through introduction of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)", Press Information Bureau, Cabinet, May 20, 2020.
32. "Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) launches another funding scheme to help the distressed MSME sector", Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Press Information Bureau, June 24, 2020.
33. Guidelines for Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt to Stressed/NPA MSMEs, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, August 19, 2020, https://msme.gov.in/sites/default/files/SubdebtBookletversion 2.pdf.
34. "The CSC operators VLEs to enable citizens to avail e-Governance services of 140 Departments through the UMANG App", Ministry of Electronics & IT, Press Information Bureau, August 26, 2020.
35. Lok Sabha Unstarred Question No. 2264, Ministry of Electronics and Information Technology, March 4, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/173/AU2264.pdf.
36. Lok Sabha Unstarred Question No. 608, Ministry of Commerce and Industry, November 20, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU608.pdf.
37. Annual Report, Ministry of Electronics and Information Technology, 2020, https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Annual_Report_2019%E2%80%9320.pdf.
38. Annual Report, Ministry of Electronics and Information Technology, 2018, https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Annual_Report_2017%E2%80%9318.pdf.
39. Electronics Manufacturing Schemes, Press Information Bureau, Ministry of Electronics and Information Technology, 2020.
40. "Guidelines for the operation of Production Linked Incentive Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing", Ministry of Electronics and Information Technology, June 1, 2020, https://meity.gov.in/writereaddata/files/PLI-Guidelines-01062020.pdf.
41. "Appraisal and Disbursement Guidelines for effective functioning of the scheme for promotion of manufacturing of electronic components and semiconductors (SPECS), Ministry of Electronics and Information Technology, June 1, 2020, https://meity.gov.in/writereaddata/files/SPECS-Guidelines-01062020.pdf.

42. "Guidelines for implementation of Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme", Ministry of Electronics and Information Technology, June 1, 2020, https://meity.gov.in/writereaddata/files/EMC-2.0-Guidelines-01062020.pdf.
43. "Cabinet approves Production Linked Incentive Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing", Union Cabinet, Press Information Bureau, March 21, 2020.
44. "Cabinet approves Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme", Union Cabinet, Press Information Bureau, March 21, 2020.
45. "Cabinet approves Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors", Union Cabinet, Press Information Bureau, March 21, 2020.
46. Lok Sabha Unstarred Question No. 1797, Ministry of Electronics and Information Technology, September 21, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/174/AU1797.pdf.
47. Lok Sabha Unstarred Question Number 619, Ministry of Defence, Government of India, September 16, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/174/AU619.pdf.
48. Preparedness of Armed Forces – Defence Production and Procurement, Estimates Committee, Lok Sabha, July 25, 2018, http://164.100.47.193/lsscommittee/Estimates/16_Estimates_29.pdf.
49. 3rd Report, Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning, Standing Committee on Defence, December 2019, http://164.100.47.193/lsscommittee/Defence/17_Defence_3.pdf.
50. Lok Sabha Unstarred Question No. 2840, Ministry of Defence, March 11, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/173/AU2840.pdf.
51. SIPRI Yearbook, 2020: Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm International
Peace Research Institute, 2020, https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/yb20_summary_en_v2.pdf.
52. Defence Acquisition Procedure, 2020, Ministry of Defence, September 30, 2020, https://www.mod.gov.in/dod/sites/default/files/DAP2030new_0.pdf.
53. "Consistent decline in Left Wing Extremism related violence in the country during last five years", Ministry of Home Affairs, Press Information Bureau, March 18, 2020.
54. PM-KISAN Dashboard, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, last accessed on January 18, 2021, https://www.pmkisan.gov.in/StateDist_Beneficiery.aspx.
55. Demand No. 1, Ministry of Agriculture, Union Budget 2020-21, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe1.pdf.
56. Report no. 6, Standing Committee on Agriculture: 'Demand for Grants (2019-20), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare', Lok Sabha, December 2019, http://164.100.47.193/lsscommittee/Agriculture/17_Agriculture_6.pdf.
57. Statement Showing Minimum Support Prices - Fixed by Government (Rs. quintal), Farmers' Portal, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 2020, https://farmer.gov.in/mspstatements.aspx.
58. Lok Sabha Unstarred Question No. 331, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, September 15, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/174/AU331.pdf.
59. Evaluation Report on Efficacy of Minimum Support Prices (MSPs), NITI Aayog, January 2016, http://www.niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/MSP-report.pdf.
60. "Year End Review 2020 of Ministry of Agriculture & Farmer Welfare", Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Press Information Bureau, January 2, 2021.
61 "Year End Review 2020- (Department of Food & Public Distribution) Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, December 29, 2020.
62. "Year End Review 2020", Press Information Bureau, Department of Food & Public Distribution Ministry of Consumer Affairs and Food & Public Distribution, December 29, 2020, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1684317.
63. "Traders to get pension coverage", Press Information Bureau, Ministry of Labour and Employment, May 31, 2019.
64. "Landmark decision taken in the first Cabinet meeting of the NDA Government offers pension coverage to crores of farmers", Press Information Bureau, Cabinet, May 31, 2019.
65. S.O. 764(E), Gazette of India, Ministry of Labour and Employment, February 7, 2019, https://labour.gov.in/sites/default/files/197105.pdf.
66. Maandhan Portal, Ministries of Labour and Employment, and Agriculture and Farmers' Welfare, last accessed in January 18, 2021, https://www.maandhan.in/.
67. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, as passed by Lok Sabha, September 22, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/122-C_2020_LS_Eng.pdf.
68. The Industrial Relations Code, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Industrial%20Relations%20Code%2C%202020.pdf.
69. The Code on Social Security, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Code%20On%20Social%20Security%2C%202020.pdf.
70. G.S.R. 684(E), Gazette of India, Ministry of Labour and Employment, October 29, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222829.pdf.
71. The Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2020, https://labour.gov.in/sites/default/files/OSH_Rules.pdf.
72. G.S.R. 684(E), Gazette of India, Ministry of Labour and Employment, October 29, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222829.pdf.
73. "India records a landmark milestone with operationalisation of more than 50,000 Ayushman Bharat Health & Wellness Centres (HWCs)", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, November 20, 2020.
74. Demand No. 42, Ministry of Health and Family Welfare, Union Budget 2020-21, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe42.pdf.
75. Dr Harsh Vardhan reviews implementation of Ayushman Bharat - PMJAY and National Digital Health Mission (NDHM), Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, November 26, 2020.
76. Accessibility, Acceptability, Affordability: A National Perspective Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana 2015, Bureau of Pharma PSUs of India, http://janaushadhi.gov.in/pmjy.aspx.
77. List of Jan Aushadhi Kendras, PMJAY Portal, August, 2020, https://pmjay.gov.in/sites/default/files/2020-08/JAK-center-list.pdf.
78. "Year End Review 2019- Ministry of Human Resource Development", Press Information Bureau, January 6, 2020.

79. Expenditure Budget, Vol. 2, Union Budget 2020-21, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe59.pdf
80 National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource Development, August 1, 2020, https://seshagun.gov.in/sites/default/files/update/NEP_Final_English.pdf.
81 Pragyata Guidelines for Digital Education, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, 2020.
82 Household Social Consumption on Education (2017-18), Ministry of Statistics and Programme Implementation, July 2020.
83. "Cabinet approves establishment of Higher Education Financing Agency for creating capital assets in higher educational institutions", Press Information Bureau, Cabinet, September 12, 2016.
84. "Year End Review 2019- Ministry of Human Resource Development", Press Information Bureau, January 6, 2020.
85. Aajeevika - National Rural Livelihoods Mission, Ministry of Rural Development, last accessed on January 5, 2021, https://aajeevika.gov.in/.
86. Demand No. 100, Ministry of Women and Child Development, Union Budget 2020-21, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe100.pdf.
87. G1: SHGs Under NRLM, Ministry of Rural Development, last accessed on January 18, 2021, https://nrlm.gov.in/shgOuterReports.do?methodName=showShgreport.
88. Unstarred Question No. 961, Lok Sabha Questions, Ministry of Health and Family Welfare, February 7, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/173/AU961.pdf.
89. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana Implementation Guidelines, Ministry of Women and Child Development, August, 2017, http://wcd.nic.in/sites/default/files/PMMVY%20Scheme%20Implementation%20Guidelines%20-%20MWCD%20%281%29_0.pdf.
90. Starred Question No. 99, Lok Sabha Questions, Ministry of Women and Child Development, February 7, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/173/AS99.pdf.
91. "Development of Women and Children", Press Information Bureau, Ministry of Women and Child Development, September 23, 2020, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1658302.
92. Scheme On Fast Track Special Courts (FTSC) For Expeditious Disposal Of Cases Of Rape And Protection Of Children Against Sexual Offences (POCSO) Act, Ministry of Law and Justice, 2019, https://doj.gov.in/sites/default/files/Fast%20Track%20Special%20Courts%20Scheme%20guidelines%202019.pdf.
93. "Year End Review-2020", Press Information Bureau, Ministry of Law and Justice, December 31, 2020, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1684945.
94. Unstarred Question No. 4225, Lok Sabha Questions, Ministry of Women and Child Development, December 13, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU4225.pdf.
95. "Nirbhaya Fund", Press Information Bureau, Ministry of Women and Child Development, February 7, 2020, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1602403.
96. Vital Stats: Parliament functioning in Monsoon Session, 2020, PRS Legislative Research, September 23, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/PRS_17LS_Monsoon_2020_Vital_Stats.pdf.
97. Vital Stats: Parliament functioning in first session of 17th Lok Sabha, PRS Legislative Research, August 7, 2019, https://www.prsindia.org/sites/default/files/Vital%20Stats-%20Budget%20Session%202019%2017%20LS.pdf.
98. Session Wrap, 17th Lok Sabha, PRS Legislative Research, 2020, https://www.prsindia.org/sessiontrack/budget-session-2020/productivity.
99. Notification No. G.S.R. 109(E) - The Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020, Ministry of Finance, February, 12, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/216109.pdf.
100. Rojer Mathew vs South Indian Bank Ltd. & Ors., Civil Appeal No. 8588 of 2019, November 13, 2019, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/9680/9680_2017_1_1501_18247_Judgement_13-Nov-2019.pdf.
101. Volume II, Report of the Task Force National Infrastructure Pipeline, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, April 30, 2020, https://dea.gov.in/sites/default/files/Report%20of%20the%20Task%20Force%20National%20Infrastructure%20Pipeline%20%28NIP%29%20-%20volume-ii_0.pdf.
102. National Infrastructure Project, India Investment Grid, Ministry of Commerce and Industry, last accessed on January 18, 2021, https://indiainvestmentgrid.gov.in/national-infrastructure-pipeline.
103. NIP Projects, India Investment Grid, Ministry of Commerce and Industry, last accessed on January 5, 2021, https://indiainvestmentgrid.gov.in/opportunities/nip-projects.
104. "Considerations under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana", Press Information Bureau, Ministry of Rural Development, September 18, 2020, https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1656170.
105. Habitations Coverage, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Ministry of Rural Development, last accessed on January 18, 2021, http://omms.nic.in/.
106. "Standing Committee on Rural Development, 2018-19, Department of Rural Development, Ministry of Rural Development" http://164.100.47.193/lsscommittee/Rural%20Development/16_Rural_Development_52.pdf.
107. Regional Connectivity Scheme - UDAN, Ministry of Civil Aviation, October 2016, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Final%20Regional%20Connectivity%20Scheme%20%28RCS%29.pdf
108. 78 New Routes Approved Under UDAN 4.0, Press Information Bureau, Ministry of Civil Aviation, August 27, 2020.
109. Monthly Report, Ministry of Civil Aviation, August, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Monthly_Summary-Aug-2020.pdf.
110. Monthly Report, Ministry of Civil Aviation, September, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Monthly-Summary-Sep-2020.pdf
111. Monthly Report, Ministry of Civil Aviation, October, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Monthly_Summary%20_Oct_2020.pdf.
112. "About 35 Lakh Passengers flown under RCS-Udan scheme till date", Press Information Bureau, Ministry of Civil Aviation, December 23, 2019.
113. India suspends all flights to and from United Kingdom, Press Information Bureau, Ministry of Civil Aviation, December 21, 2020.
114. Fare bands for domestic flights extended upto 24th February, 2021, Press Information Bureau, Ministry of Civil Aviation, November 6, 2020.
115. AV. 11011/1/2020-US(AG) Office-MOCA, Ministry of Civil Aviation, March 23, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Revised-%20COVID-19%20-%20Order%20under%20Section%208B.pdf.

116. Special Window for Completion of Affordable and Mid-Income Housing (Swamih Investment Fund) Created, Press Information Bureau, Ministry of Finance, September 16, 2020.
117. 'FAQs on Special Window for Funding Stalled Affordable and Middle-Income Housing Project as Approved by Union Cabinet on November 6, 2019', Press Information Bureau, Ministry of Finance, November 7, 2019.
118. Major Interventions to Boost the Economy, Press Information Bureau, December 11, 2019, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Major%20Government%20Interventions-v4.pdf.
119. Progress so Far- SWAMIH Fund, Ministry of Finance, December 1, 2020, https://twitter.com/FinMinIndia/status/1337601013318963200/photo/1.
120. Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin, Ministry of Rural Development, last accessed on January 18, 2021, https://www.iay.nic.in/netiay/home.aspx.
121. PMAY(U) Achievement, Ministry of Housing and Urban Affairs, last accessed on January 18, 2021, https://pmay-urban.gov.in/uploads/progress-pdfs/1.pdf.
122. Demand No. 57, Ministry of Housing and Urban Affairs, Union Budget 2020-21, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe57.pdf.
123. Demand No. 85, Department of Rural Development, Union Budget 2020-21, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe85.pdf.
124 "Rs70,000 crore boost to housing sector and middle income group through extension of Credit Linked Subsidy Scheme for MIG under PMAY(Urban)", Press Information Bureau, Ministry of Finance, May 14, 2020.
125 Lok Sabha Unstarred Question Number 1714, Ministry Of Housing And Urban Affairs, November 28, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU1714.pdf.
126. Swachh Bharat Mission (Grameen) Dashboard, Department of Drinking Water and Sanitation, last accessed on January 18, 2020, https://sbm.gov.in/sbmdashboard/IHHL.aspx.
127. Swachh Bharat Mission - Gramin in States/UTs, Standing Committee on Rural Development, July 19, 2018, http://164.100.47.193/lsscommittee/Rural%20Development/16_Rural_Development_51.pdf.
128. PPAC's Snapshot of India's Oil and Gas data, Ministry of Petroleum and Analysis Cell, November, 2020, https://www.ppac.gov.in/WriteReadData/Reports/202012231048227556898SnapshotofIndiasOilGasdataNovember2020_Rv.pdf.
129. "Prime Minister Garib Kalyan Package-Progress So Far", Press Information Bureau, Ministry of Finance, June 20, 2020.
130. 100 Report No.14 of 2019 - Performance Audit of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Comptroller and Auditor General of India, December 11, 2019.
131. "Cabinet approves Capital Grant as Viability Gap Funding to Indradhanush Gas Grid Limited for setting up the North East Natural Gas Pipeline Grid", Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, January 8, 2020.
132. "Year End Review -2020-Ministry of Petroleum & Natural Gas", Press Information Bureau, Ministry of Petroleum & Natural Gas, December 31, 2020.
133. "Year End Review 2020 – Ministry of Power", Press Information Bureau, Ministry of Power, December 30, 2020.
134. "MNRE: Year End Review-2020", Press Information Bureau, Ministry of New and Renewable Energy, December 31, 2020.
135. "MNRE: Year End Review-2019", Press Information Bureau, Ministry of New and Renewable Energy, January 9, 2020.
136. Pradhan Mantri Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyaan (PM-KUSUM), Ministry of New and Renewable Energy, https://mnre.gov.in/solar/schemes/.
137. Order No. 32/645/2017-SPV Division – "Scale-up and expansion of Pradhan Mantri Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyaan (PM-KUSUM), Ministry of New and Renewable Energy, November 4, 2020, https://mnre.gov.in/img/documents/uploads/file_f-1604916951612.pdf.
138. Status of tap water supply in rural homes, Jal Jeevan Mission, Ministry of Jal Shakti, last accessed on January 18, 2021, https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx.
139. Demand no. 61, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Union Budget 2020-21, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe61.pdf.
140. Lok Sabha Unstarred Question No.2837, Ministry of Jal Shakti, December 5, 2019, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU2837.pdf.
141. Lok Sabha Unstarred Question No. 1879, Ministry of Jal Shakti, September 22, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/174/AU1879.pdf.
142. "Year End Review: Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti", Press Information Bureau, Ministry of Jal Shakti, December29, 2020.
143. "20th Standing Committee on Water Resources (2017-18)", Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Demand for Grants (2018-19), http://164.100.47.193/lsscommittee/Water%20Resources/16_Water_Resources_20.pdf.
144. Sustainable development and climate change, Volume 2, Economic Survey 2018-19. https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/vol2chapter/echap05_vol2.pdf.
145. "Government launches National Clean Air Programme (NCAP)", Press Information Bureau, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, January 10, 2019, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=187400.
146. "Long-Term, Time-Bound, National Level Strategy to Tackle Air Pollution-National Clean Air Programme (NCAP)", Press Information Bureau, Ministry of Housing & Urban Affairs, September 16, 2020.
147. Unstarred Question No. 1041, Lok Sabha Questions, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, September 18, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/174/AU1041.pdf.
148. Demand No. 25, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Union Budget 2020-21, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe25.pdf.
149. The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance, 2020, Ministry of Law and Justice, October 28, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222804.pdf.
150. Unstarred Question No. 1800, Lok Sabha Questions, Ministry of Communications, September 21, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/174/AU1800.pdf.

151. BharatNet MIS, Ministry of Communication, last accessed on January 18, 2021, http://www.bbnl.nic.in/.
152. The Personal Data Protection Bill, Ministry of Electronics and Information Technology, December 11, 2019, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/373_2019_LS_Eng.pdf.
153. "Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019 seeks views and suggestions", Press Information Bureau, Ministry of Parliament Affairs, February 3, 2020, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1601695.
154. Unstarred Question No. 2259, Lok Sabha Questions, Department of Space, March 4, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/173/AU2259.pdf.